

सिविल मिसेलेनियस
माननीय न्यायालय, एच. आर. सोधी, जे.

एम/एस. सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड, -याचिकाकर्ता

बनाम

विभाग आयुक्त ई. टी. सी.- उत्तरदाता

सिविल रिट नं. 1970 का 2549

22 सितंबर, 1970

पंजाब नगरपालिका अधिनियम (1911 का 3)-धारा 65 और 85-कर अधिरोपण के विरुद्ध अपील-आक्षेपित कर का जमा-चाहे अपील के मनोरंजन के लिए पूर्ववर्ती शर्त हो।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 85 की उपधारा (2) को सरल रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी कर के अधिरोपण के विरुद्ध अपील पर तब तक विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि अपील दायर किए जाने तक अपील की विषय वस्तु के अतिरिक्त कोई कर अदा नहीं किया गया हो। इस प्रकार आक्षेपित कर का जमा करना अपील की संस्था के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं है और यह केवल तभी है जब अपीलार्थी नगरपालिका समिति को देय अन्य करों के संबंध में चूककर्ता है कि उसे अधिनियम के तहत किसी कर के लिए नए दायित्व को चुनौती देने की अनुमति नहीं है। अधिनियम की योजना यह प्रतीत होती है कि नगरपालिका का निवासी जिसे कई करों का भुगतान करना पड़ सकता है, लेकिन वह सभी या उनमें से किसी के भुगतान में चूक करता है, उसे नए कर के खिलाफ अपील करने का निरंकुश अधिकार नहीं दिया जाएगा, जब वह पहले से ही करों के मामले में चूककर्ता है। उपधारा (2) में "नगरपालिका कर" पद से पहले "अन्य" शब्द का प्रयोग अर्थहीन नहीं है। इसका उपयोग स्पष्ट रूप से कर निर्धारण के विपरीत किया गया है।

(Para 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिका में अनुरोध किया गया है कि 22 मई, 1970 को अंबाला के उपायुक्त के आदेश को निरस्त करने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए और उन्हें योग्यता के आधार पर अपील पर सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए और प्रशासक, नगर पालिका, यमुनानगर को 2 करोड़ रुपये की राशि की वसूली से रोका जाए। 11, 251.31 वर्ष 1970-71 के लिए वर्ष 1969-70 में उप-आयुक्त अंबाला द्वारा वर्ष 1969-70 की अपील की सुनवाई और विनिश्चय करने तक प्राप्त मूल्यांकन के आधार पर।

याचिकाकर्ता के लिए हीरा लाल सिबल और एस. सी. सिबल, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए रूप चंद चौधरी, अधिवक्ता।

निर्णय

- 1) यह रिट याचिका मेसर्स द्वारा दायर की गई है। सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड, यमुनानगर, जिसे इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया है, ने 22 मई, 1970 को अंबाला के उपायुक्त द्वारा पारित एक आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने हाउस-टैक्स लगाने के खिलाफ कंपनी की अपील को इस आधार पर सुनने से इनकार कर दिया था कि कर की राशि जमा नहीं की गई थी।
- 2) याचिकाकर्ता कंपनी ने यमुनानगर की नगरपालिका सीमा के भीतर अच्छी संपत्ति की बुवाई की, जहां वह अपना व्यवसाय कर रही है। पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के तहत नगरपालिका समिति द्वारा

हाउस-टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया था, जैसा कि अद्यतन और इसके बाद अधिनियम कहा जाता है। अनंतिम मूल्यांकन सूची तैयार करने के बाद, वर्ष 1969-70 के लिए प्रस्तावित पुनर्मूल्यांकन पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए अधिनियम की धारा 65 (1) में परिकल्पित एक सार्वजनिक सूचना 3 नवंबर, 1969 को प्रकाशित की गई थी। सरस्वती चीनी मिलों और भारतीय चीनी और सामान्य इंजीनियरिंग निगम नाम की अपनी दोनों संस्थाओं की संपत्तियों के संबंध में नगरपालिका समिति द्वारा वार्षिक किराये के मूल्य के निर्धारण के संबंध में कंपनी द्वारा आपत्तियां दी गईं। नगरपालिका समिति ने चीनी मिलों की संपत्तियों के लिए किराये के मूल्य का आकलन किया था। इसके अलावा इंडियन शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के लिए 2,96,650 रुपये है। 54, 720। आंशिक रूप से अनुमत आपत्तियों को सुनने के बाद, मूल्यांकन को अंततः 20 जनवरी, 1970 को आवश्यक संशोधनों के साथ निपटाया गया। यह ज्ञात नहीं है कि अंतिम सूची वास्तव में कब प्रकाशित की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता कंपनी ने 18 फरवरी, 1970 को अधिनियम की धारा 84 के तहत उपायुक्त को एक अपील दायर की। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपील सीमा के भीतर थी। आक्षेपित कर की वसूली पर रोक लगाने के लिए 19 फरवरी, 1970 को उपायुक्त को एक आवेदन दिया गया था और उन्होंने 20 फरवरी, 1970 को इसकी अनुमति दी थी। नगरपालिका समिति ने लगभग एक महीने के बाद स्थगन आदेश को समाप्त करने के लिए आवेदन किया, जिसकी सूचना कंपनी को 19 मार्च, 1970 को जारी की गई थी। दल 20 मार्च, 1970 को उपायुक्त के समक्ष पेश हुए और पहले दी गई रोक को हटा दिया गया। इसके बाद कंपनी ने 24 मार्च, 1970 को पूरा कर जमा कर दिया और अपील की सुनवाई 22 मई, 1970 को हुई, जब विवादित आदेश दिया गया था।

- 3) अतः इस न्यायालय को वर्तमान याचिका जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, अपील की सुनवाई से इनकार करने वाले उपायुक्त के आदेश को एक उपायुक्त रिट या निर्देश जारी करके रद्द करने का अनुरोध किया जाता है।
- 4) याचिकाकर्ता के विद्वत वकील श्री एच. एल. सिब्बल ने कई आधारों पर आक्षेपित आदेश की वैधता पर हमला किया है, लेकिन उनके द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि उनके साथ व्यवहार करना अनावश्यक है यदि यह न्यायालय धारा 85 की व्याख्या पर यह विचार रखता है कि कानून की कोई आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम के तहत अपील में चुनौती दिए जाने वाले कर को अपील पर विचार करने से पहले जमा किया जाना चाहिए। धारा 85 में अंतर्विष्ट सुसंगत उपबंध निम्नानुसार है: –
 “85. (1) किसी भूमि या भवन पर कर के संबंध में कोई अपील तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वह धारा 66 या धारा 68 द्वारा विहित सूचना के प्रकाशन के एक मास के भीतर या धारा 69 के अधीन, यथास्थिति, किसी अंतिम आदेश की तारीख के बाद नहीं की जाती है और किसी अन्य कर के संबंध में कोई अपील तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कर की मांग किए जाने के समय से एक मास के भीतर नहीं की जाती है:
 बशर्ते कि इस धारा द्वारा इसके लिए विहित अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील स्वीकार की जा सकती है यदि अपीलार्थी उस अधिकारी को संतुष्ट करता है जिसके समक्ष अपील को प्राथमिकता दी जाती है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।
 (2) किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी ने ऐसी अपील की तारीख तक समिति को अपने द्वारा देय अन्य सभी नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया है।”
- 5) यह किसी का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता से नगर समिति को देय किसी अन्य कर का भुगतान तब नहीं किया गया था जब विचाराधीन अपील को उपायुक्त, प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था 1- वास्तव में, वर्ष 1969-70 के लिए गृह-कर, जिसके लिए दायित्व का विरोध किया जा रहा था, भी 24 मार्च, 1970 को अपील के लंबित रहने के दौरान जमा किया गया था, जब स्थगन आदेश को खाली कर दिया गया था। उपधारा (2) के सरल पठन से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि किसी कर के अधिरोपण के विरुद्ध अपील को तब तक अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि अपील दायर किए जाने तक अपील की विषय वस्तु के अतिरिक्त कुछ कर का भुगतान नहीं किया गया हो। इस प्रकार आक्षेपित कर का जमा

करना अपील की संस्था के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं है और यह केवल तभी है जब अपीलार्थी नगरपालिका समिति को देय अन्य करों के संबंध में चूककर्ता है कि उसे अधिनियम के तहत किसी कर के लिए नए दायित्व को चुनौती देने की अनुमति नहीं है। नगरपालिका समिति द्वारा कराधान की शक्ति भूमि, भवन, पशु, वाहन, व्यवसाय या आवास और कई अन्य मामलों सहित विभिन्न विषयों तक फैली हुई है। अधिनियम की योजना यह प्रतीत होती है कि नगरपालिका का निवासी जिसे कई करों का भुगतान करना पड़ सकता है, लेकिन वह सभी या उनमें से किसी के भुगतान में चूक करता है, उसे नए कर के खिलाफ अपील करने का निर्बाध अधिकार नहीं दिया जाएगा, जब वह पहले से ही करों के मामले में चूककर्ता है। उपधारा (2) में "नगरपालिका कर" पद के पूर्ववर्ती "अन्य" शब्द का प्रयोग अर्थहीन नहीं है। इसका उपयोग स्पष्ट रूप से कर निर्धारण के विपरीत किया गया है। यदि विधायिका का इरादा था कि निर्धारित कर की राशि जमा की जानी चाहिए थी, तो यह स्पष्ट रूप से कहा गया होगा जैसा कि हम कई अन्य कानूनों में पाते हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 20 के प्रावधान में, यह अधिनियमित किया गया है कि "ऐसे प्राधिकारी द्वारा तब तक कोई अपील नहीं की जाएगी जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि विक्रेता पर निर्धारित कर की राशि और जुर्माना, यदि कोई हो, का भुगतान कर दिया गया है।" अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (2) में प्रयुक्त अन्य भाषा किसी ऐसे प्रयोजन के बिना नहीं हो सकती है, जो यह प्रतीत होता है कि नगरपालिका का बकाया नगरपालिका के किसी निवासी के हाथों में जमा नहीं होना चाहिए और यदि वह व्यतिक्रमी नहीं है तो वह किसी भी पूर्व शर्तों के बिना किसी नए या नए कर के विरुद्ध अपील के माध्यम से अपना उपचार प्राप्त कर सकता है। मेरे विचार से, यह एकमात्र व्याख्या है जो अधिनियम की नीति और सार्वजनिक हित के अनुरूप है। यह वित्तीय निहितार्थों से संबंधित एक राजकोषीय मामला है और नागरिक के लिए लाभकारी व्याख्या को हमेशा रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब यह उपयोग किए गए शब्दों के सामान्य अर्थ के अनुरूप हो। मेरी राय में, कोई भी अन्य व्याख्या, प्रकट बेतुकी बात की ओर ले जाएगी और "अन्य" शब्द को इसके सामान्य अर्थ के अलावा एक विविध और संशोधित शब्द देगी जिसका विधायिका द्वारा इरादा नहीं किया जा सकता था। इसलिए, उपायुक्त त्रुटि में था और इस आधार पर कंपनी की अपील को सुनने से इनकार करके अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा कि कर जमा नहीं किया गया था।

- 6) इस मामले में एक और दृष्टिकोण भी है। उसी उपायुक्त प्रत्यर्थी द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण कर जमा नहीं किया गया था। जैसे ही आदेश को खाली किया गया, नगर समिति के आवेदन पर याचिकाकर्ता ने कर की राशि का भुगतान कर दिया। इस मामले में, धारा 84 के तहत अपीलों की सुनवाई करने वाले प्राधिकरण की अंतर्निहित शक्ति पर यह कहना आवश्यक नहीं है कि उसके खिलाफ अपील किए गए आदेश या प्रस्ताव के संचालन पर रोक लगाई जाए, जब हम पाते हैं कि कानून स्वयं इस बिंदु पर चुप है। हालाँकि, मैं यह देखने से बच नहीं सकता कि किसी भी नागरिक को अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित गलत आदेश के कारण पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए, जो बाद में गलती का एहसास करता है और उस आदेश का लाभ वापस लेता है। कर की राशि का भुगतान स्थगन आदेश के कारण नहीं किया गया था और जब आदेश की छुट्टी पर इसका भुगतान किया गया था तो उपायुक्त का कर्तव्य था कि वह कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर अपील का निपटान करे, चाहे उसके द्वारा दी गई रोक उसकी क्षमता के भीतर न हो।
- 7) परिणामस्वरूप, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है, प्रत्यर्थी 1 का 22 मई, 1970 को किया गया आदेश रद्द कर दिया जाता है, और यह निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर अपील की सुनवाई करे। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नूह, हरियाणा